186

- (1) Review by the Government on the working of the National Coal Development Corporation Limited, Ranchi, for the year 1967-68.
- (2) Annual Report of the National Coal Development Corporation Limited, Ranchi, for the year 1967-68 along with the Audited Accounts and the Comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library. See No. LT-758/69]

ESTIMATES COMMITTEE

STATEMENT RE: REPLIES TO RECOM-MENDATIONS

SHRI P. VENKATASUBBAIAH
(Nandyal): I beg to lay on the Table a State
ment showing final replies to recommendations
included in Chapter V of the Sixty-third
Report of the Estimates Committee which
were not furnished by Government in time
for inclusion in the Report.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE FORTY-FIFTH REPORT

SHRI M. R. MASANI (Rajkot): I beg to present the Forty-fifth Report of the Public Accounts Committee on action taken by Government on the recommendations of the Public Accounts Committee contained in their Thirty-fourth Report on Wasteful Expenditure on Government Publications.

PUBLIC UNDERTAKINGS COMMITTEE THIRTY-FIRST REPORT

SHRI G. S. DHILLON (Taran Taran): I beg to present the Thirty-first Report of the Committee on Public Undertakings on action taken by the Government on the recommendations contained in the Twenty-eighth Report of the Committee on Public Undertakings (Third Lok Sabha) on the Head Office of Hindustan Steel Limited.

12.06 hrs.

MOTION: RE SUSPENSION OF RULE 338 IN RESPECT OF CONSTITUTION (TWENTY-SECOND AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN): I beg to move the following:

"That Rule 338 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its application to the motion for taking into consideration of the Constitution (Twenty-second Amendment) Bill, 1969, be suspended".

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That Rule 338 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its application to the motion for taking into consideration of the Constitution (Twenty-second Amendment) Bill, 1969, be suspended".

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : अध्यक्ष महोदय....

MR. SPEAKER: I thought he had spoken on that,

Shri Vajpayee had proposed some amendment.

भी भीचन्द गोयल : अध्यक्ष महोदय, चिक आज यह विषय सुनिश्चित रूप में सदन के सामने आया है इसलिये मैं इसका विरोध करना चाहता हं। नियम 338 सोच समभकर बनाया गया है कि जिस विषय को सदन ने एकबार एक सत्र में अस्वीकार किया हो तो उसको दुबारा उसी सत्र में अनुमति नहीं भिलनी चाहिये। मैं समभता हं कि यदि कोई उचित और आवश्यक काम हो, देश की भलाई का कोई काम किया जा रहा हो, जिससे कि नियम का उल्लंघन होता हो तब नियम से छट्टी दिलाई जाय, यह बात समक्त में आ सकती है, परन्तू आज नियम से वच निकलने का अर्थ यह है कि देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात् दो वर्षों के अन्दर सरदार पटेल ने जो काम किया उसको हम समाप्त करने जा रहे हैं। आज सारा देश इस सदन की तरफ देख रहा है कि आगे हम इस देश को छोटे-छोटे टकडों में विभक्त करेंगे या देश के अन्दर एकता कायम करेंगे।

पिछली बार जब यह बिल हाउस में पास नहीं हो सका तब मैं समभता हूं कि सरकार जागरूक नहीं रही। सरकार का अपना दोष या। आजवह अपने दोषों से छुट्टी लेने के लिये फिर से सदन से इस बात की अनुमति ले, [श्री श्रीचन्द गोयल]

मैं सममता हूं कि वह अनुचित बात है, विशेषकर जब कि गृहमंत्री ने इस बात का कारण नहीं बतलाया कि क्यों इस काम में इतनी जल्दबाजी की जा रही है। जब वर्षों से यह मामला चल रहा था, तब दो महीने बाद जब अगला सत्र होगा तब यह चीज आ सकती थी। इसमें इतनी जल्दबाजी की कौन सी बात थी? इसको बाद में सदन में पेश करना चाहियेथा।

इस कारण से मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

SHRI S, 'M. BANERJEE (Kanpur): I want to oppose him.

श्री अब्बुलगनी डार (गुड़गांव): अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि इस बक्त देश एक मोड़ पर है। मोड़ यह आया है कि देश को तबाही की तरफ जाना है या उसको सम्भलना है। मुभको किसी से विरोध नहीं है। अगर पहाड़ी भाइयों को इन्साफ नहीं मिला है तो उनको इन्साफ मिलना चाहिये। लेकिन इसके यह माने नहीं हैं कि कोई यहां आये और कहे कि चूंकि उसको इन्साफ नहीं मिला इसलिये वह अलग स्टेट चाहते हैं बजाय यह कहने के कि जिस स्टेट ने गुनाह किया है, उनके साथ अच्छा सुलूक नहीं किया, उनके रीजन की तरफ ध्यान नहीं दिया, वह उसकी तरफ ध्यान दे।

जो हमारा सैंटर है, यूनियन गवनंमेंट है उसको चाहिये या कि वह आसाम गवनंमेंट की मदद करती, बजाय इसके वह आज मुल्क के दुकड़े-दुकड़े करने की तरफ जा रही है। मेरा ईमानदारी से यह खयाल है कि सेंट्रल गवनंमेंट वाले यह समभते हैं कि अगर छोटे-छोटे दुकड़े करते जायेंगे तो सेंटर का दबदबा ज्यादा रहेगा। अगर बड़ी-बड़ी स्टेट्स रहेंगी तो वह बात नहीं रहेगी। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता कि इसमें कोई सदाकत है। मैं समभता हूं कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सूबा है कि एक मुल्क कहला सकता है। वह बड़े-बड़े देशों से भी बड़ा सूबा है, लेकिन उसकी तरफ देखने की हुकूमत की जुर्रेत नहीं है। वह उसकी तरफ आंख उठा कर भी नहीं देख सकते।

यह सब मैं इसिलये कह रहा हूं कि आखिर क्यों यह जल्दबाजी की जा रही है? जब छः महीने बाद अगले सेशन में यह लाया जा सकता है तब इसको जल्दी लाने की कोशिश क्यों की जा रही है? मैं उन्हें समभाना चाहता हूं कि अगर वह इस तरह से करते जायेंगे तो वह हमेशा मजबूर होंगे इसके लिये और उनको यह नहीं करना चाहिये। मि॰ चव्हाण यह कहते हैं कि एक के बाद एक राज्य बनते चले गये पंडित जी के समय में। उनके जमाने में आन्ध्र बना। मुक्तको उसकी खुशी हुई। आन्ध्र से अलग अगर तेलंगाना बनेगा तब शायद मुक्तको उसकी भी खुशी होगी क्योंकि मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने का फैसला हो गया है।

अध्यक्ष महोवय : माननीय सदस्य मेरिट्स में जा रहे हैं।

श्री अब्दुलगनी डार: यह तो मैंने प्री-एम्बल के तौर पर अर्ज किया है।

इस एमेंडमेंट के विना देश में उलटपुलट हो जाएगी क्या इसलिए श्री चव्हाण आईन की खिलाफ वर्जी करना चाहते हैं? उनको क्यों जल्दी हुई ? क्यों वह चाहते हैं कि इसको अभी पास किया जाए? मैं समभता हं कि यह जो रास्ता है यह बिल्कूल गलत है। मैं समभता हूं कि देशवासियों को पूरा मौका दिया जाना चाहिये कि वे इस पर सोचें, इस पर विचार करें। उनकी पार्टी को भी सोचना चाहिये और जो दूसरी पार्टीज यहां हैं, उनको भी सोचना चाहिये। मैं देखता हूं कि लैफ्ट पार्टी जो है वह इस मामले में तो कांग्रेस की बड़ी मदद कर रही है लेकिन तेलंगाना के मामले में मुखालिफत कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों चव्हाण साहब रूल्ज का उल्लंघन करना चाहते हैं। इन रूल्ज को उन्होंने खुद बनाया है। रूल कहता है कि इसे सैशन में नहीं ला सकते हैं। उनको इस सैशन में इसको नहीं लाना चाहिये था और आपको भी इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिये।

کیوں پرجلدہا زی کی جارہی ہے جب المہینے بعد
اگلے سیشن میں پر لایا جا سکتا ہے تب الس کو
جلدی لانے کی کوئشش کیوں کی جارہی ہے میں
انہیں سمجھانا چا تہا ہوں کر اگر زہ اس طرح سعے
کرتے جائیں گئے تو وہ ہمینہ کیجود ہوں کے اس کے
لئے اوران کو پرنہیں کرنا چاہیئے ممثر ججہ ہا ن
پر کہتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک واجمیہ بغتے چلے
گئے نیڈت جی کے سعم میں ۔ ان کے زمانے
میں آ مذمعرا بنا ۔ مجھ کو اس کی خوشی ہوئی ۔ آندھوا
سے الگ اگر تلنگانہ بنے گا تب شاید مجھ کو اس
کیمی خوشی ہوگی کیونکہ ملک کوتباہی کی طرف
لے جانے کا فیصلہ ہوگیا ہے۔

ادهیکش مهودے مانینه سدسید میرمیش می جادہے ہیں۔

فری عبدالغنی ڈار۔ یہ تویں نے میری ایمب کے طور پرعرض کیاہے۔

اس ایمند منٹ کے بنا دلین میں المث پلے ہو جائے گئی کیا اس کے تسری جوہائی کی اس کے تسری جوہائی کئی اس کے تسری جوہائی کئی جلدی ہوئی کیوں وہ چاہتے ہیں ان کو کیوں وہ چاہتے ہیں کہ اس کو اسمی پاکس کیا جائے گئے کہ وہ اس حاسیوں کو پورامو تعہ ویا جانا جا تھے کہ وہ اس پر سوچیں ۔ اس پر وچا دکریں ۔ ان کی پارٹی کو بھی سوچنا چاہتے کہ اور جو دوسری پارٹیزیہاں کھی سوچنا چاہتے ہیں دیکھتا ہوں کا میں ان کو کھی سوچنا چاہتے ہیں دیکھتا ہوں کہ کھتا ہوں کے کھتا ہوں کھتا ہوں کھتا ہوں کھتے ہیں دیکھتا ہوں کھتا ہوں کھتے ہیں دیکھتا ہوں کھتا ہوں کھتا

[شری عبدالغنی ڈار (گڑ گانوس) ا د معیکش مہودے ۔ میں بڑے

ا د هیکش مهودے سی بڑے ادب سے سوض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دلیں ایک موڑ پرہے موڑ پرہے کہ آیا دلیں کو تباہی کی طوف جانا ہے یا اس کو سنجملنا ہے۔ مجھ کو کسی سیے ورد دھ نہیں ہے۔ اگر بہاڑی بھائیول کو انھا نہیں الا ہے تو ان کو انھان کے بیمونی نہیں ہیں کہ کوئی بہاں آئے اور کھے کہ جس اسٹیٹ نے گناہ کیا ہے۔ ان کے ساتھ کہ جس اسٹیٹ نے گناہ کیا ہے۔ ان کے ساتھ مہیں دیا۔ وہ اس کی طرف دھیا نہیں دیا۔ وہ اس کی طرف دھیان دے۔

یہ سب میں اص لئے کہردہاموں کر آ خسر

کریدش پارٹی جو ہے دہ اس معاطیم تو کائوس کی ٹری مدکررہی ہے لیکن تیلنگا نہ کے معاط میں مخالفت کر ہی ہے۔ میں مبا ننا چاہتا ہوں کوکوں جو ہان صاحب دولز کا انتھن کراچاہتے ہیں۔ ان دولز کو انہوں نے تو د بنایا ہے۔ رول ہیں۔ ان کو اس سیشن میں نہیں لاکسکتے ہیں۔ ان کو اس سیشن میں اس کو نہیں لا اباج ہیں۔ تعادادر آپ کو معی اس کی امبا زمت نہیں دئی چاہیئے

MR. SPEAKER: This is a motion under rule 388 for the suspension of rule 338. The hon. Member speaks of U. P., Andhar and other places. One should not speak on the merits of the Bill now. The question is:

"That Rule 338 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its application to the motion for taking into consideration of the Constitution (Twenty-second Amendment) Bill, 1969 be suspended."

The motion was adopted

12.12 hrs.

CONSTITUTION (TWENTY-SECOND AMENDMENT) BILL

MR. SPEAKER: The House will now take up the Constitution Amendment Bill for which two hours had been allotted. I propose to put the motion for consideration to vote at about 3 P.M. and thereafter the clauses and the motion for passing between 3 and 4 P.M. I say this so that the House may know the time and they may all be here.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN): I move :*

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

With your permission, Mr. Speaker, I shall just repeat what I said before.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY (Cooch-Behar): On a point of order. The whole Bill brought before us gives us the idea for having a new State or one more State under our Constitution. Though it has been worded most guardedly--it says 'an autonomous State' for all intents and purposes it creates a new State. My point of order arises under rule 376 (1). Under article 2 of our Constitution, Parliament may by law admit into the Union or establish, new States on such terms and conditions as it thinks fit. Under article 3, Parliament may by law form a new State by separation of territories from any State or by uniting two or more States or parts of States or by uniting any territory to a part of any State. There is a provision which says:

"Provided that no Bill for the purpose shall be introduced in either House of Parliament except on the recommendation of the President and unless, where the proposal contained in the Bill affects the area, boundaries or name of any of the States, the Bill has been referred by the President to the Legislature of that State for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference or within such further period as the President may allow and the period so specified or allowed has expired."

We are having a new State by the name of 'autonomous State'.

MR. SPEAKER: There is no point of order; you can speak on this later on, not now.

SHRI B. K. DASCHOWDHURY: I am finishing in one minute.

To have a new State, it requires the recommendation of the President. Not only that. The recommendation of the State legislature is also necessary. In this case, we find in the Bill that the recommendation of the President has been obtained under article 117 (1) and (3) but no such recommendation has been obtained under

^{*}Moved with the recommendation of the President.